ISSN-0970-0718

जागृति

वर्ष:60 अंक:3 मुम्बई फरवरी 2016

मन की बात

वर्ष 2016 की अपनी पहली “मन की बात” में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा खादी को बढ़ावा देने हेतु लोगों से पूरा सहयोग देने का आह्वान

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई

ISSN-0970-0718

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष 60 अंक 3 मुम्बई फरवरी 2016

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष
अरुण कुमार झा

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

अवर उप सम्पादक
अमृता सोम मुखर्जी

अवर हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार - अनुप खोडस्कर

कलाकार - दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्स: 022-26719465
ई-मेल: jagritikvic@gmail.com वेबसाईट: www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित
सम्पादक: के. सुब्बाराव राव

सदस्यता शुल्क

वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रू. 100/-
वर्ष के लिये सदस्यता शुल्क	:	रू. 250/-

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 27

- "मन की बात": माननीय प्रधान मंत्री द्वारा खादी को बढ़ावा देने हेतु लोगों से पूरा सहयोग देने का आह्वान
- खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े मेरे बहनों और भाइयों के नाम माननीय प्रधान मंत्री का पत्र
- गाँधी जी के सपनों को मूर्तरूप देना सरकार की प्राथमिकता है- कलराज मिश्र
- गाजियाबाद में एमएसएमई मंत्री द्वारा खादी प्रदर्शनी "खादी बाज़ार" का उदघाटन
- आयोग मुख्यालय में 67 वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया
- रेलवे को खादी उत्पादों की आपूर्ति हेतु आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार श्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की।
- आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना, गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेन्द्रसिंह चूडासामा के साथ रणपुर, गुजरात में आयोजित एक स्नेह मिलन समारोह में।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएँ
- दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा चरखा'
- हरित वस्त्र" के नाम से जानी जाएगी.......अब खादी
- साधना के लिए चरखा और सूत न केवल साधन है, बल्कि उसकी साधना और उद्देश्य भी है – मनोज पाठक
- उत्तर प्रदेश में युबाओं के लिए 25 इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का वाराणसी दौरा
- आयोग के राज्य कार्यालय, गंगटोक में 67वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया
- भारत और मॉरिशस के मध्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु पहली संयुक्त समिति की बैठक
- अण्डमान निकोबार खादी बोर्ड द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत डीएलटीएफसी की 51वीं बैठक
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग देगा मॉरीशस को सहयोग
- गांधी, खादी-चरखा और रोजगार- राघवेन्द्र त्रिपाठी, यूनीवार्ता
- कताई कार्य, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्तों का भाग्य बदल देगा
- सत्य पॉल ने पेश किए मराठवाड़ा खादी परिधान
- ए.जी. राव को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु श्रेष्ठ समन्वयक पुरस्कार
- मुख्यालय में कार्यालय अधीक्षकों के लिए हिन्दी कार्यशाला सम्पन्न
- नासिक में दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित
- विभागीय उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक

खादी क्षेत्र की सुर्खियां 28 से 31

मन की बात

मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसके जरिये भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। वर्ष 2016 की अपनी पहली "मन की बात" में माननीय प्रधान मंत्री ने खादी को बढ़ावा देने हेतु लोगों से पूरा सहयोग देने का आह्वान किया।

मेरे प्यारे देशवासियों,

कुछ दिन पहले मैं सरदार पटेल के विचारों को पढ़ रहा था। तो कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। खादी के संबंध में सरदार पटेल ने कहा है, हिन्दुस्तान की आजादी खादी में ही है, हिन्दुस्तान की सभ्यता भी खादी में ही है, हिन्दुस्तान में जिसे हम परम धर्म मानते हैं, वह अहिंसा खादी में ही है और हिन्दुस्तान के किसान, जिनके लिए आप इतनी भावना दिखाते हैं, उनका कल्याण भी खादी में ही है। सरदार साहब सरल भाषा में सीधी बात बताने के आदी थे और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने खादी का महात्म्य बताया है। मैंने कल 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्य तिथि पर देश में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ, मैंने पत्र

लिख करके पहुँचने का प्रयास किया। वैसे पूज्य बापू विज्ञान के पक्षकार थे, तो मैंने भी टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों ऐसे भाईयों-बहनों तक पहुँचने का प्रयास किया है। खादी अब एक symbol बना है, एक अलग पहचान बना है। अब खादी युवा पीढ़ी के भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है और खास करके जो-जो holistic health care और organic की तरफ झुकाव रखते हैं, उनके लिए तो एक उत्तम उपाय बन गया है।

फैशन के रूप में भी खादी ने अपनी जगह बनाई है और मैं खादी से जुड़े लोगों का अभिनन्दन करता हूँ कि उन्होंने खादी में नयापन लाने के लिए भरपूर प्रयास किया है। अर्थव्यवस्था में बाजार का अपना महत्व है। खादी के लिए भी भावात्मक जगह के साथ-साथ बाजार में भी जगह बनाना अनिवार्य हो गया है। जब मैंने लोगों से कहा कि अनेक प्रकार के fabrics आपके पास हैं, तो एक खादी भी तो होना चाहिये और ये बात लोगों के गले उतर रही है कि हाँ भाई, खादीधारी तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर दसों प्रकार के fabric हैं, तो एक और हो जाए। लेकिन साथ-साथ मेरी बात से सरकार में भी एक सकारात्मक माहौल पनप रहा है। बहुत सालों पहले सरकार में खादी का भरपूर उपयोग होता था। लेकिन धीरे-धीरे आधुनिकता के नाम पर ये सब खत्म होता गया और खादी से जुड़े हुए हमारे गरीब लोग बेरोजगार होते गए। खादी में करोड़ों लोगों को रोजगार देने की ताकत है।

पिछले दिनों रेल मंत्रालय, पुलिस विभाग, भारतीय नौसेना, उत्तराखण्ड का डाक-विभाग ऐसे कई सरकारी संस्थानों ने खादी के उपयोग में बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छे Initiative लिए हैं और मुझे बताया गया कि सरकारी विभागों के इस प्रयासों के परिणामस्वरूप खादी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, इस requirement को पूरा करने के लिए, सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त extra - 18 लाख मानव दिन का रोजगार generate होगा। 18 lakh man-days, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा jump होगा। पूज्य बापू भी हमेशा Technology के up-gradation के प्रति बहुत ही सजग थे और आग्रही भी थे और तभी तो हमारा चरखा विकसित होते-होते यहाँ पहुँचा है। इन दिनों solar का उपयोग करते हुए चरखा चलाना, solar energy चरखे के साथ जोड़ना बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। उसके कारण मेहनत कम हुई है, उत्पादन बढ़ा है और qualitative गुणात्मक परिवर्तन भी आया है। खास करके solar चरखे के लिए लोग मुझे बहुत सारी चिट्ठियाँ भेजते रहते हैं। राजस्थान के दौसा से गीता देवी, कोमल देवी और बिहार के नवादा जिले की साधना देवी ने मुझे पत्र लिखकर कहा है कि solar चरखे के कारण उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हमारी आय double हो गयी है और हमारा जो सूत है, उसके प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। ये सारी बातें एक नया उत्साह बढ़ाती हैं, और 30 जनवरी, पूज्य बापू को जब स्मरण करते हैं, तो मैं फिर एक बार दोहराऊँगा - इतना तो अवश्य करें कि अपने ढेर सारे कपड़ों में एक खादी भी रहे, इसके आग्रही बनें।

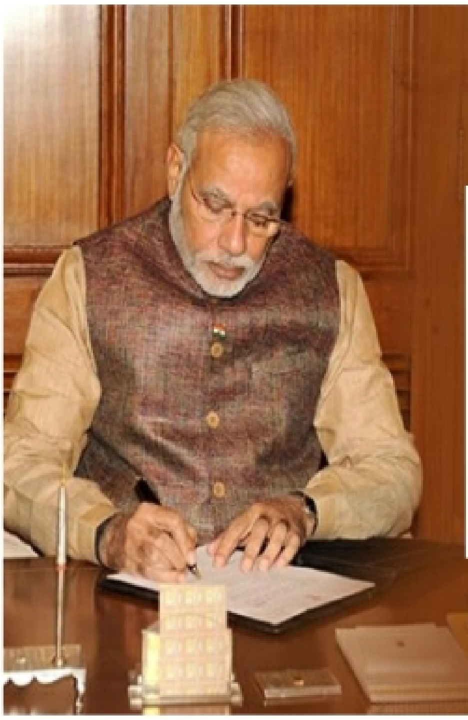

माननीय प्रधान मंत्री का पत्र

खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े मेरे बहनों और भाइयों,

आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गांधी जी का सपना था कि प्रत्येक भारतवासी स्वावलंबी बने। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने हमें खादी का मंत्र दिया।

मेरे लिए यह अत्यंत खुशी की बात है कि सरकार के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं और आपके द्वारा तैयार किए गए खादी के उत्पादों का उपयोग करने के लिये विभिन्न सरकारी संस्थान आगे आ रहे हैं। इनमें रेल मंत्रालय, पुलिस विभाग, भारतीय नौ सेना, डाक विभाग सहित अन्य सरकारी संस्थान शामिल हैं। मुझे बताया गया कि इन संस्थानों की माँग को पूरा करने के लिए लगभग 18 लाख मानव दिनों का अतिरिक्त रोजगार खादी के क्षेत्र में उपलब्ध होगा और प्रत्येक कारीगर की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।

आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली खादी आज एक फैशन परिधान बन गई है। नवगठित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग नए अवसरों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे आपको विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ आसानी से मिल सके।

आयोग द्वारा सोलर चरखा और सोलर लूम से उत्पादन के सफल प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कत्तिन बुनकर पहले से कम मेहनत में अधिक उत्पादन कर सकें और उन्हें दोगुनी आमदनी हो।

हम भारत के गांवों में खादी और ग्रामोद्योग का नेटवर्क करना चाहते हैं, ताकि लोगों को रोजगार से जोड़कर गांवों के प्रत्येक परिवार को सबल बनाया जा सके।

- नरेन्द्र मोदी

लखनऊ में राज्य स्तरीय पी.एम.ई.जी.पी. कार्यशाला आयोजित

गाँधी जी के सपनों को मूर्तरूप देना सरकार की प्राथमिकता है

-कलराज मिश्र

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए इसके क्रियान्वयन में गति देने के उद्देश्य से दिनांक 06.01.2016 को गन्ना संस्थान, लखनऊ के प्रेक्षागृह में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन श्री कलराज मिश्र, माननीय सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया।

कार्यशाला में डा. अनूप कुमार पुजारी, सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, श्री विनय कुमार सक्सेना, माननीय अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री जयप्रकाश तोमर, सदस्य, खादी ग्रामोद्योग आयोग (मध्य क्षेत्र),, डा. रजनीश दूबे, प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई), उ.प्र. शासन, श्रीमती नीना शर्मा, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर, डा. मोनिका एस. गर्ग, प्रमुख सचिव (खादी एवं ग्रामोद्योग), उ.प्र. शासन, श्री मनमोहन चौधरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ, श्री के. एन. जनार्दन, राष्ट्रीय समन्वयक, आरसेटी एवं श्री आर. एस. पाण्डेय, राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लखनऊ, राज्य के सभी जिला उद्योग केन्द्रों के आयुक्त (उद्योग), प्रदेश के सभी अग्रणी जिला प्रबंधक, सभी बैंकों के स्थानीय प्रमुख,प्रदेश में स्थित सभी आरसेटी के निदेशक तथा योजना के क्रियान्वय से संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया ।

कार्यशाला के उद्घाटन के पश्चात कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री कलराज मिश्र, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देश में उपलब्ध कच्चे माल की उपलब्धता का उपयोग करते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया था और कहा था कि जब तक देशवासी उपलब्ध कच्चे माल का सदुपयोग करेंगे, तो स्वावलम्बन के आधार पर देश में स्वदेशी की भावना जागृत होती रहेगी। गाँधी जी के मनोभावों का मूर्तरूप प्रदान करने हेतु महात्मा गाँधी के सपनों व ग्राम स्वराज के नारे को बल प्रदान के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे देश की मिट्टी में उद्यमिता विद्यमान है, हमारे यहाँ के लोग आत्मनिर्भर होकर कार्य करना चाहते हैं, उद्यमिता के भाव को जागृत करना ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है। माननीय मंत्री ने आगे कहा कि उ.प्र. बड़ा प्रदेश है, अपेक्षा के अनुरूप मार्जिन मनी राशि प्राप्त नहीं हो पायी है। इस योजना के क्रियान्वयन में उ.प्र. में जितनी धनराशि की जरूरत होगी, वह हम भारत सरकार की तरफ से देने के लिए तैयार हैं, पर प्राप्त धनराशि का समुचित उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार प्राथमिकता के आधार पर गाँधी जी के सपनों को मूर्तरूप देना चाहती है। देश के बहुमुखी विकास के लिए देश और प्रदेश का समन्वय आवश्यक है जब मेक इन यूपी सफल होगा तभी मेक इन इण्डिया भी सफल होगा।

श्री मिश्र ने यह भी कहा कि देश में लघु उद्योगों के विस्तार के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योग आधारित यू.ए.एम. प्रणाली लागू की गयी है, जिसमें 20 बिन्दुओं के ऑनलाईन फार्मेट भरने से स्वत: ही उद्यमियों को उद्योग पंजीकरण प्राप्त हो जायेगा तथा इन्हें सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी । पी.एम.ई.जी.पी. कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अति महत्वपूर्ण योजना है, इसी से स्वावलम्बन प्राप्त होगा एवं बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर का नारा फलीभूत होगा।

उन्होंने उपस्थित भागार्थियों का आह्वान किया कि यह योजना अच्छे ढ़ंग से कार्यान्वित होनी चाहिए और इसमें व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं मंत्रालय स्तर पर विचार करते हुए निराकरण हेतु सभी उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

डा. अनूप कुमार पुजारी, सचिव, सू.ल.म.उ. मंत्रालय, भारत सरकार ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए इस कार्यशाला में आये हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों का सहयोग व सुझाव अपेक्षित है। हम सबको साथ मिलकर योजना की बेहतरी के लिए कार्य करना होगा। हमें योजना के डिजाईन की कमियों के बारे में कार्यशाला के दौरान जो भी सुझाव आयेंगे, उस पर मंत्रालय विचार करते हुए समुचित निदान करेगा।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कार्यशाला में आये हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारियों, जिला उद्योग केन्द्र, उ.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, बैंकर्स से आग्रह किया कि इस योजना में आ रही बाधाओं को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत सरकार की प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना है, जिसके द्वारा लाखों लोगों को रोजगार देकर स्वावलम्बी बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि बैंकों के नीरसता के कारण योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक नहीं हो पर रहा है। बैंकों को योजना के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि बैंक जब आर.टी.जी.एस. के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित कर सकती हैं, तो ई-ट्रेकिंग के द्वारा सारे विवरण भरकर मार्जिन मनी राशि का स्थानान्तरण क्यों नहीं किया जा सकता है। सारी गतिविधियाँ ऑनलाईन होने से कार्य में पारदर्शिता आयेगी। श्री सक्सेना ने यह भी कहा कि ईडीपी प्रशिक्षण सभी चयनित उद्यमियों को देना बेहतर होगा। हमारे अधिकारियों की एक संयुक्त टीम, जिसमें वित्त पोषित बैंक के प्रबन्धक, संबंधित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं आयोग के जिला समन्वयक होंगे, के द्वारा कराया जाना चाहिए ताकि किसी भी विसंगति के लिए जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि पीएमईजीपी के अन्तर्गत योजना लागत 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने पर विचार किया जाना चाहिए । योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु कारगर रणनीति पर जोर देते हुए कहा कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, हमारा प्रयास है कि समाज का आखिरी व्यक्ति जो गरीब है, उसके साथ ऐसा व्यवहार न करें कि वह जहाँ खड़ा है, वहीं खड़ा रहे। इस योजना में आ रही अड़चनों को कम कर, प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर योजना की गति को तीव्र किया जाना चाहिए, जिससे कि गरीब से गरीब तबके के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके।

डा. रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव (सूक्ष्म लद्यु एवं मध्यम उद्यम), उ.प्र. ने इस अवसर पर कहा कि पीएमईजीपी के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों का भौतिक सत्यापन वित्त पोषक बैंक के शाखा प्रबन्धक एवं तीनों कार्यदायी एजेन्सियों के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से कराया जाना चाहिए। उ.प्र. हेतु वर्ष 2015-16 के लिए अतिरिक्त मार्जिन मनी राशि जारी की जाय ताकि बैंकों द्वारा जितने उद्यमियों की पीएमईजीपी के अन्तर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की गई है उन सभी उद्यमियों को बिना विलम्ब के मार्जिनमनी अनुदान राशि समय से प्राप्त हो सके। पीएमईजीपी के अन्तर्गत मार्जिन मनी अनुदान का लॉक-इन पीरियड तीन वर्ष से कम कर, दो वर्ष किया जाय।

श्रीमती नीना शर्मा, आयुक्त एवं निदेशक(उद्योग), उ.प्र. ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हेतु पीएमईजीपी के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मार्जिनमनी अनुदान का आवंटित लक्ष्य राज्य के जनसंख्या एवं उद्यमिता की सम्भावनाओं की तुलना में काफी कम है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य में पीएमईजीपी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कोई "कंटीजेन्सी फण्ड" आवंटित नहीं है जिस कारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा उसकी मानिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। अत: सभी कार्यदायी अभिकरणों को आवंटित मार्जिन मनी का कम से कम 5 प्रतिशत राशि कंटीजेन्सी खर्च हेतु उपलब्ध कराया जाय।

इस अवसर पर आयोग के सदस्य (म.क्षे.), श्री जय प्रकाश तोमर ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यदल समिति द्वारा चयनित पीएमईजीपी के सभी आवेदन पत्र बैंक द्वारा स्वीकृत किये जाने चाहिए क्योंकि चयन के समय जिला अग्रणी प्रबन्धक बैंक के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहते हैं।

अन्त में श्री गुलाम हुसैन, मंडलीय निदेशक, खादी ग्रामोद्योग आयोग, मेरठ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यशाला का समापन किया गया।

गाजियाबाद में केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा खादी प्रदर्शनी “खादी बाज़ार” का उदघाटन

गाजियाबाद, 21 जनवरी, 2016: केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री कलराज मिश्र ने आज गाजियाबाद में खादी पीएमईजीपी प्रदर्शनी “खादी बाजार-2016” का उद्घाटन किया।

प्रदर्शनी के उद्घाटन पश्चात खादी बाजार 2016 में माननीय मंत्री महोदय ने प्रदर्शनी के प्रतिभागियों एवं प्रदर्शकों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री ने कहा कि खादी उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार वाराणसी में एक खादी भवन बनाने की योजना बना रही है।

उन्होंने बताया कि खादी बिक्री मुख्य रूप से पिछले वर्ष से अपने चरम पर है क्योंकि सभी आयु वर्ग के लोग अब खादी खरीद रहे हैं। खादी बिक्री के 2014-15 की पहली छमाही के आंकड़े अपने पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट पर थे। इन्हीं आंकड़ों में वर्ष 2014-15 की (सितंबर अप्रैल) दूसरी छमाही में अचानक उछाल आया। जबकि पहली दो तिमाहियों (2013-14) में बिक्री 500 करोड़ रुपये से घटकर 417 करोड़ रुपये रह गयी थी। हालांकि, अगली दो तिमाहियों 2014-15 में यही आंकड़ा 581 रुपये से ऊपर चला गया।

आयोग मुख्यालय में 67 वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

मुख्यालय, मुंबई: 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास के लिए स्वर्णिम दिन है। वर्ष 1950 में इसी दिन हमारे देश का संविधान अस्तित्व में आया और हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। देश में अंतत: महात्मा गांधी एवं आजादी के लिए अपने प्राणों की आहूति देने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी के स्वप्न को पूरा करते हुए 26 जनवरी, 1950 को देश में गणतंत्र लागू हुआ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भी इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए देश का 67वां गणतंत्र दिवस मनाया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश ने मुख्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

इस अवसर पर आयोग की वित्तीय सलाहकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम खादी की बेहतरी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि खादी हमारी देश की आजादी का पूरक है। देश में विविधता के पश्चात भी यह दिन लोगों में देश भक्ति के जोश का संचार कर उन्हें एक साथ रखता है।

इस अवसर पर आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एस.राव, श्री वाई . के. बारामतिकर, श्री एस. के. सिन्हा, कार्यक्रम निदेशक एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने आयोग परिसर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया।

रेलवे को खादी उत्पादों की आपूर्ति हेतु आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने दिनांक 5 जनवरी, 2016 को माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार श्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री ने खादी क्षेत्र को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना ने दिनांक 15.01.2016 को गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेन्द्रसिंह चूडासामा के साथ रणपुर, गुजरात में आयोजित एक स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएँ

खादी और ग्रामोद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण कुमार झा ने 13 जनवरी, 2016 को आयोग मुख्यालय मुंबई के प्रार्थना कक्ष में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आयोजित नव वर्ष शुभकामना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर आयोग की वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री मोहित जैन, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाय. के बारामतिकर एवं श्री एस. के. सिन्हा व अन्य कार्यक्रम निदेशक तथा अधिकारी गण उपस्थित थे।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए मख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं तथा कर्मचारियों को बधाई देते हुए जानकारी दी कि आयोग में भर्ती संबंधी नियम (रिक्रूटमेंट रूल) की प्रतीक्षा लगभग समाप्त होने वाली है जिससे पदोन्नति से जुड़ी बाधाओं को समाप्त किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि राजस्व अर्जित करने की दिशा में आयोग ने जो कदम उठाये थे उनके सकारात्मक परिणाम अब परिलक्षित होने लगे हैं, जो सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत उसकी संस्तुति को खादी और ग्रामोद्योग आयोग में लागू करने के लिए हितकर सिद्ध होगा।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की नवनियुक्त वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश व आयोग के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री मोहित जैन ने भी आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों को नये वर्ष की शुभकामनाएं दी।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा चरखा

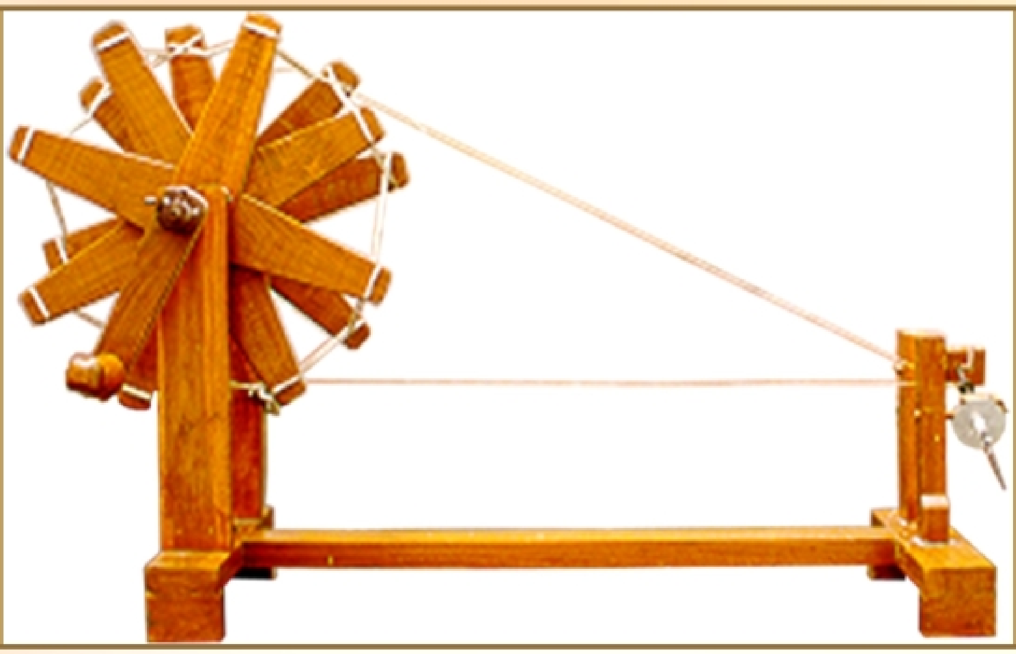

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का सूत कातने का चरखा प्रदर्शित किया जाएगा जो आजादी के आंदोलन में स्वावलंबन का प्रतीक बन गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने चर्खे को एकजुटता के यंत्र के रूप में प्रयोग किया। वह खुद सूत कातते थे और इसे भारत के आत्मनिर्भरता का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर भारतीय ग्रामोद्योग और खादी के प्रतीक चरखे की 27 फुट लंबी और 15 फुट प्रतिकृति स्थापित की जाएगी।

पिछले सप्ताह, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना तथा जी.एम.आर. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आई. प्रभाकर राव के बीच हुई एक बैठक में एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के गेट नं.4 व 5 के बीच प्रस्थान स्थल पर चरखे को स्थापित करने हेतु जगह उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर स्थापित होने वाला यह चरखा काष्ठ और लोहे से निर्मित होगा। चरखा भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है और मौजूदा वर्ष 2016 महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने का है। इसलिए यह वर्ष खादी और इसके सबसे सशक्त उपकरण चरखे के लिए महत्वपूर्ण है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि यह विश्व का सबसे बड़ा चरखा होगा और यह प्रतिदिन 1.50 लाख देशी तथा विदेशी यात्रियों को भारतीयता से परिचित

"हरित वस्त्र" के नाम से जानी जाएगी..अब खादी

- खादी को "कार्वन रहित" वैश्विक उत्पाद वनाने के लिए सरकार अग्रसर
- परियोजना की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री की स्वीकृति
- खादी कपड़ों की सबसे बड़ी विशेषत:"हाथ बुना और हाथ कता" होना
- खादी की मांग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देन।
- खादी उत्पादों की वाजार क्षमता रु. 40,000 करोड़

हमारी सरकार खादी को "शून्य दोष"-"कार्बन रहित" वाला वैश्विक उत्पाद बनाने के लिए अग्रसर है। सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए सरकार सोलर चरखों को देश भर में लोकप्रिय कर रही है जिससे हाथ से कती हुई खादी को "कार्बन रहित" हरित वस्त्र के रूप में पहचान मिल सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह ने कहा, इस परियोजना की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिल गयी है तथा इसे विशेष कार्यक्रम के आधार पर बिहार के नवादा जिले के खनवा गांव में प्रारम्भ भी किया जा चुका है। श्री गिरिराज सिंह ने देश में खादी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए प्रमुख दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं एवं इसके लिए वह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से भी मिलेंगे। खादी कपड़ों की सबसे बड़ी विशेषता उनका "हाथ बुना और हाथ कता" होना है और विपणन की दृष्टि से इसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा।

श्री गिरिराज सिंह ने बताया कि हम इस हरित वस्त्र का उत्पादन और विपणन अन्य रेडिमेड वस्त्रों की तरह करेंगे। हम इसके लिए निजी साझेदारों से सहयोग लेंगे। विभिन्न परिधान हाउस इस माह में हमें अपनी रिपोर्ट देंगे। अरविंद मिल्स और लीवाइस जैसे ब्राण्ड खादी से जींस बना रहे हैं, हम खादी की मांग को अंतर्राष्ट्रीय रूप देना चाहते हैं और इसके लिए 2.5 करोड़ प्रवासी भारतीय हमारे लक्ष्य हैं।

उन्होंने आगे बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पूरे देश भर से 7000 खादी और ग्रामोद्योगी बिक्री केन्द्रों को नवीन रूप देने की योजना बनाई है। अध्ययन के अनुसार खादी उत्पादों की बाजार क्षमता रु. 40,000 करोड़ की है। सरकार स्कूलों में खादी के वस्त्रों की शुरुआत करने पर भी जोर दे रही है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस नए प्रयास से भी रु. 18,000 करोड़ तक का लाभ होगा। केंद्र, रु. 6,000 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के 300 स्कूलो में सर्वे करवाया है जिसमें 70 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है।

साधना के लिए चरखा और सूत न केवल साधन है, बल्कि उसकी साधना और उद्देश्य भी है

मनोज पाठक

आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी क्रम में बिहार के नवादा जिले के खनवां गांव की रहने वाली साधना देवी अपनी मेहनत और समझ की बदौलत घर की चारदीवारी को लांघ, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" तक पहुंच गईं, बल्कि महिलाओं के लिए एक मॉडल भी बन गई हैं। आज केवल खनवां गांव में ही नहीं, साधना की चर्चा समूचे राज्य और देश में हो रही है।

मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात" में एक पत्र का उल्लेख करते हुए साधना का जिक्र किया था। वैसे खनवां की साधना को इसका अहसास भी नहीं था कि उसके द्वारा भेजा गया प्रधानमंत्री को एक पत्र उनके मन की बात में शामिल हो जाएगा।

सातवीं पास साधना के लिए आज चरखा और सूत न केवल स्वावलंबी बनने का साधन है, बल्कि उसकी साधना और उद्देश्य भी है।

खनवां गांव के गिरामपुर टोला निवासी साधना के पति अरविंद सिंह की तबीयत आठ महीने पूर्व अचानक खराब हो गई, तब दूसरों की मदद लेकर साधना ने अपने पति का इलाज करवाया। इस क्रम में साधना की जमापूंजी तो खत्म हो ही गई थी,

दूसरे की मदद लेना भी उसे बुरा लगा।

साधना कहती हैं, 'मैं रोजगार के लिए किसी विकल्प की तलाश कर रही थी, इसी दौरान गांव में सोलर चरखा का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। यह मेरे लिए आज वरदान साबित हो रहा है।"

उन्होंने सोलर चरखा से सूत कातने का प्रशिक्षण लिया और आज यह उसके परिवार की कमाई का जरिया बन गया। साधना प्रतिदिन इस चरखे से करीब 200 रुपये कमाती है।

केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत नवादा के खनवां गांव को गोद लिया था। पांच माह पहले खादी ग्रामोद्योग की मदद से खनवा में सोलर चरखे का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। पहले चरण में प्रशिक्षित 50 महिलाओं को चरखे भी उपलब्ध कराए गए। महिलाएं कच्चे माल से सूत कातती हैं और तैयार सूत को खादी ग्रामोद्योग को देती हैं।

मंत्री और नवादा के सांसद श्री सिंह ने आईएएनएस से कहा, "प्रधानमंत्री मोदी आम लोगों की बात करते हैं, यही कारण है कि वे जनमानस के नेता हैं। गांव की एक महिला के पत्र का जिक्र कर उन्होंने उसे देश की महिलाओं की उन्नति से जोड़ा। सोलर चरखा आज सच में इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए खुशी लाने का साधन बन गया है।"

साधना ने बताया कि उसने दो महीने में 40 किलो सूत की कताई की है, जिससे आठ हजार रुपये की आमदनी हुई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार के नरहट प्रखंड के खनवां निवासी 35 वर्षीया साधना ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर सोलर चरखा से हो रहे फायदे की जानकारी दी थी। उस पत्र में मजदूरी बढ़ाने की फरियाद भी थी। रविवार को प्रधानमंत्री ने जब रेडियो पर साधना की चर्चा की, तब साधना की खुशी का ठिकाना न रहा।

साधना ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझ जैसे निर्धन की फरियाद सुनी। मेरी मेहनत की सार्वजनिक रूप से चर्चा की। हालांकि उस समय मैं सूत कात रही थी, इसलिए खुद तो नहीं सुन पाई, लेकिन लोगों ने जब बताया, तब मुझे काफी खुशी हुई। यह मेरी खुशकिस्मती है।"

खनवां पंचायत की मुखिया बेबी देवी भी अपने गांव की महिला की चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने से प्रसन्न हैं। बेबी ने खुशी जाहिर करते हुए आईएएनएस से कहा, 'प्रधानमंत्री ने खनवां गांव का जिक्र कर गांव का मान बढ़ाया है। सोलर चरखा लाचार महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। निश्चित रूप से गांव की प्रधानमंत्री द्वारा चर्चा किए जाने से गांव की और उन्नति होगी।"

बेबी कहती हैं कि पहले गांव की महिलाएं सिर्फ घरेलू कार्यो तक ही सीमित थीं, लेकिन अब स्वावलंबी बनने की उनमें चाहत जगी है।

साभार: खादी न्यूज़

उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए 25 इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र ने लखनऊ में दिनांक 06 जनवरी, 2016 को गन्ना संस्थान, लखनऊ के प्रेक्षागृह में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण और शहरी युवाओं को सेवाभिमुखी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपने प्रतिष्ठित कार्यक्रमों के अंतर्गत आजीविका प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में 25 इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना करने जा रहा है।

श्री कलराज मिश्र ने आगे बताया कि ये इंक्यूबेशन केन्द्र अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में स्थापित किए जाएगें और राज्य सरकार द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। मंत्री महोदय खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कार्यशाला की अध्यक्षता करने के लिए लखनऊ में उपस्थित थे।

राज्य के ग्रामीण भागों में इंक्यूबेशन केन्द्रों को स्थापित किया जाएगा, इसके लिए जमीन राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सम्पूर्ण देश में 100 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में इस प्रकार के 10 सेंटरों के लिए जमीन आबंटित की गई है। वाराणसी और देवरिया में दो केन्द्रों ने कार्य करना प्रारम्भ भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार 25 केंद्र स्थापित किए जाएगें, इसमें तकनीकी और गैर-तकनीकी संबन्धित विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाएगें।

श्री मिश्र ने आगे बताया कि युवाओं को इंक्यूबेशन केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उन्हें, अपना उद्योग स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय बैंकों से ऋण प्रदान किया जाएगा और जो युवा नौकरी करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को बेहतर स्थान में नियोजित करने हेतु मदद प्रदान की जाएगी।

इन केन्द्रों में लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग, दर्जी कार्य और ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम तथा अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

मंत्रालय ने इंक्यूबेशन केंद्र में सम्पूर्ण देश के आठ लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्यांक निर्धारित किया है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सरकार, एमएसएमई उद्योगों के लिए डिजिटल रोज़गार कार्यालय स्थापित करने की भी योजना बना रही है।

मंत्री महोदय ने आगे जानकारी दी कि इन रोजगार कार्यालयों में उद्यमियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवाभिमुखी कंम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में बताते हुए श्री मिश्र ने कहा कि कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों में नवीनता लाने के लिए इस योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

लखनऊ में, डॉ. शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, आई.ई.टी. परिसर एंव महिला विद्यालय स्नातकोत्तर कॉलेज में इंक्युबेशन केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का वाराणसी दौरा

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने आयोग के मंडलीय कार्यालय, वाराणसी, का दौरा 9 और 10 दिसंबर, 2015 को किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के द्वारा नए रोजगार तलाशने की संभावनाओं पर मंथन किया।

जयापुर ग्राम का दौरा: अध्यक्ष महोदय ने 10 दिसम्बर 2015 को वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जयापुर ग्राम का दौरा किया तथा यहाँ की ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गा देवी और मेसर्स जन कल्याण परिषद (खादी और ग्रामोद्योग से सीधी सहायता प्राप्त संस्थान) के सचिव श्री सुरेंद्र सिंह से मुलाकात की और उनके साथ चर्चा करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

जन कल्याण खादी ग्रामोद्योग परिषद, वाराणसी के सचिव गांव में खादी की कताई और बुनाई जैसी गतिविधियां शुरू करेंगे और इसमें 18 वर्ष के ऊपर 25 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। ग्राम प्रधान उम्मीदवारों को चिन्हित कर उनके प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करेंगे।

प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वह प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 15,000/- रुपये की लागत वाले नए मॉडल चरखा (एनएमसी) प्रदान करेंगे जिसे वह घर पर ही चलाकर प्रति दिन 80 से 100 रुपये तक कमा सकते है। 5-6 बुनकरों को 35,000/- रुपये लागत वाला नवीनतम विकसित ग्राम लक्ष्मी करघा उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि वह प्रतिदिन 120-150/- रुपये तक कमा सकते है। खादी के कत्तिनों और बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा योजना, वर्क शेड योजना के तहत लाया जाएगा। खादी संस्थाएं उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराएंगी तथा उनसे तैयार सूत और कपड़ा लेगी एवं उनके बैंक अकाउंट के द्वारा उन्हें घर पर ही मेहनताना भी दिया जाएगा।

इसके साथ ही 18 वर्ष के ऊपर 10 से 15 लड़कियों को सिलाई/डिजाइनिंग/कढ़ाई में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिससे वह फैंसी वस्त्रों का उत्पादन कर पायें तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़कर रेडीमेड वस्त्र इत्यादि तैयार कर सकें।

3) किसानों और ग्रामवासी जिनके पास पर्याप्त पशु हैं उन्हें बायोगैस संयंत्र दिया जाएगा जिससे उन्हें प्रकाश, रसोई गैस, जैव खाद उपलब्ध हो सके और गांव की साफ-सफाई और स्वच्छता में सुधार हो।

सभी उपरोक्त गतिविधियां अगले 30-45 दिनों में शुरू हो जाएंगी।

सेवापुरी ग्राम का दौरा: अध्यक्ष महोदय ने सेवापुरी ग्राम में एक प्रशिक्षण केंद्र सहित दो खादी संस्थानों का दौरा किया। प्रशिक्षण केन्द्र में कताई, बुनाई, चमड़ा, हस्तनिर्मित कागज उत्पाद, मसाला प्रसंस्करण, मिट्टी के बर्तन, मधुमक्खी पालन, सिलाई, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर, कागज रूपांतरण, अगरबत्ती बनाने और मोमबत्ती बनाने के प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कर इन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा तथा ग्रामीण युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित कर सतत रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और खादी संस्थाओं को पीएमईजीपी और अन्य उद्यमी कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य दो खादी संस्थाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा जिससे लगभग 500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जा सके।

भट्ठी ग्राम का दौरा: भट्ठी गांव वाराणसी में लोहता के पास स्थित है, जहां लगभग 80 पारंपरिक कुम्हार परिवार और 150 कारीगर, पारंपरिक कुम्हारी उद्योग से जुड़े हुए हैं। यह कच्चे माल, विपणन और कम आमदनी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन कुम्हारों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्फूर्ति योजना से जोड़ा जाएगा जिससे प्रशिक्षण, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उत्पाद डिजाइन, नवीनतम प्रौद्योगिकी सहायता, विपणन और प्रदर्शनी आदि के माध्यम से वह अपनी आय बढ़ा सकते है। 3 से 4 माह के अंदर इसके पुनरुत्थान की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी।

आयोग के राज्य कार्यालय, गंगटोक में 67वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया

26 जनवरी, 2016 को आयोग के राज्य कार्यालय, गंगटोक में 67वां गणतंत्र दिवस समारोह मनााया गया, इस अवसर पर कार्यालय के विकास अधिकारी प्रभारी डा. एस. के. भुयान ने कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर कार्यालय के सभी पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत का गायन किया गया।

गणतंत्र दिवस समारोह में आसपास के आम जनों के साथ स्थानीय स्कूल के विधार्थियों ने भी भाग लिया।

भारत और मॉरिशस के मध्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु पहली संयुक्त समिति की बैठक

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग संबंधी पहली संयुक्त समिति की बैठक आज 21 जनवरी, 2016 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। ये क्षेत्र दोनों देशों के बीच 13 दिसम्बर, 2015 को हुए समझौते के अनुरूप हैं। सहयोग के जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के जरिए क्षमता निर्माण, सक्षम क्षेत्रों का सर्वेक्षण, प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल, विपणन, प्रदर्शनी एवं व्यापार मेलों का आयोजन, व्यापार गतिविधियों का आदान-प्रदान, वित्त तक आसान पहुंच शामिल हैं।

दोनों देशों ने उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा कॉयर, खादी और हस्तशिल्प वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर भी सहमति व्यक्त की गई। मॉरिशस ने भारत को विशेष रूप से बायोफार्मिंग प्रौद्योगिकी प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के आदान-प्रदान पर भी सहमति व्यक्त की है।

बैठक में मॉरिशस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के व्यापार, उद्यम एवं सहकारिता मंत्री महामहिम श्री सूमिलदुथ सुनील भोला और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने किया तथा भारतीय पक्ष की तरफ से बैठक की सह-अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने की।

अण्डमान निकोबार खादी बोर्ड द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत डीएलटीएफसी की 51वीं बैठक

आयोग की पीएमईजीपी योजना के तहत उत्तर और मध्य अंडमान जिले से प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निपटान करने हेतु 11 जनवरी 2016 को जिला कार्यालय, मायाबंदर में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की 51 वीं बैठक श्री अर्वा गोपी कृष्ण, आईएएस, उपायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग देगा मॉरिशस को सहयोग

भारत और मॉरिशस के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए मॉरिशस गणराज्य के व्यापार, उद्यम और सहकारिता मंत्री, श्री सूमिलदथ सुनील भोलाह और मॉरिशस गणराज्य के व्यापार, उद्यम और सहकारिता मंत्रालय के स्थायी सचिव श्री वासू पुटचे ने 19 जनवरी, 2016 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्रमशः श्री के.एस. राव, श्री एस.के. सिन्हा, श्री वाई. के. बारामतिकर तथा आयोग के अन्य कार्यक्रम निदेशकों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के ढेबरभाई सभाकक्ष में बैठक की।

इस बैठक में उन्होंने मॉरिशस में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से रोजगार सृजन, उद्यमिता, विपणन, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों का आयोजन, व्यापार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, क्लस्टर समूहों का विकास, युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

श्रीमती उषा सुरेश ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया एवं आयोग और इसके वर्तमान विकास के बारे में एक संक्षिप्त

परिचय दिया। श्री के. एस. राव ने खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र की व्यापकता और इसके विकास के बारे में विस्तार से बताया। श्री एस.के. सिन्हा ने पावरपॉइंट प्रदर्शन के माध्यम से "खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक सिंहावलोकन" कि प्रस्तुति की और आयोग की संभावनाओं और भविष्य पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही मधुमक्खी पालन और हाथ कागज पर तैयार फिल्मों को भी बैठक में दिखाया गया।

श्री सूमिलदथ सुनील भोलाह ने अपने संबोधन में कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का आज विश्व में अभूतपूर्व योगदान है और यह युवाओं को आकर्षित कर रहा है।

यह क्षेत्र न केवल रोजगार सृजन में सहायक है बल्कि यह स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य प्रसंस्करण, हस्तनिर्मित कागज और जैव खेती के संयुक्त उपक्रम से मॉरिशस जैसे छोटे से देश में रोजगार के विस्तृत अवसर उत्पन्न होंगे।

गांधी, खादी-चरखा और रोजगार

भारत की आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाला खादी चरखा देश में रोजगार के सृजन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक दूरदृष्टा थे इसलिए उन्होंने पहले ही खादी के महत्व को समझ लिया था और स्वयं चरखा चला कर सूत कातना शुरू कर दिया था। गांधीजी चरखे को, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता की आर्थिक निर्भरता का प्रतीक मानते थे।

महात्मा गांधी के चरखा चलाने का असर यह हुआ कि लोग विदेशी कपडों को त्याग कर स्वयं चरखा चला कर धागा बनाते और भारत में बनी खादी को शान से पहनते, इससे ब्रिटिश हुकूमत परेशान हो गयी क्योंकि उनका कपड़ा भारत में बिकना लगभग बंद हो गया।......... समय बदल गया...........और चरखे का स्वरूप भी बदल गया लेकिन इस चरखे ने कल भी लोगों की आश्यकताओं को पूरा किया था और आज भी इससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं।

वर्तमान समय में कई प्रकार के चरखे बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन सौर ऊर्जा से चलने वाला सबसे नया सोलर चरखा मिलना शुरू हो गया है। इस चरखे से कम समय में अधिक सूत काता जा सकता है। इसमें बिजली की खपत नहीं होगी जिससे लागत में कमी आयेगी और साथ ही सौर ऊर्जा से चलने के कारण उत्पादन बढ़ेगा, जिससे लोगों की आय में बढ़ोतरी होगा।

हमारे देश में जनसंख्या को देखते हुए बेरोजगारी बहुत अधिक है और बेरोज़गारी के कारण लोग परेशान हैं। बेरोजगारी युवाओं के लिए अभिशाप है कभी कभी यही युवक गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। सिर्फ बेरोजगार युवा ही नहीं परेशान हैं बल्कि अन्नदाता-किसान भी परेशान हैं। हमारी कृषि प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है यदि बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होती है यदि बारिश अच्छी नहीं हुई तो किसान परेशान हो जाते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाडा में पिछले तीन वर्ष से बारिश नहीं होने के कारण किसान आर्थिक बोझ से परेशान हैं और अब तक कई किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं।

ऐसी परिस्थिति में यदि परेशान किसान और बेरोज़गार लोग यदि चर्खे से सूत कातना शुरू करें, तो वे प्रतिमाह 10 से 15 हजार रूपये की आमदनी आसानी से कर सकते हैं और पूरे परिवार का पालन कर सकते हैं।

जो किसान मराठवाडा में फसल के नष्ट होने के कारण और कर्ज से परेशान हो कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं यदि उनके परिवार में एक भी चर्खा उपलब्ध हो तो उन्हें कृषि के अतिरिक्त प्रति माह परिवार का खर्च चलाने के लिए आमदनी हो सकती है और किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, लोगों तक जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता है। खादी चरखा अपनाकर देश के करोड़ों लोग बहुत कम समय में रोजगार पा सकते हैं लेकिन इसे बढ़ावा देने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, वरन् समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। परिवार में यदि वर्ष में एक जोड़ी खादी कपड़ा खरीदा जाय तो बेरोज़गार लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है।

बेरोजगारी को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा और स्वयं भी जागृत होना होगा क्योंकि जब तक हम स्वयं नहीं जागेंगे तब तक कोई भी आंदोलन कारगर साबित नहीं होगा। बेरोज़गार लोगों को आज सरकारें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं इसलिए इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए स्वयं पहल कर जानकारी एकत्र करें और बेरोजगारी को दूर भगाएं।

हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खादी को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड रहे हैं इसलिए आशा है कि इस क्षेत्र में करोड़ों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा।

- राघवेन्द्र त्रिपाठी, यूनीवार्ता

कताई कार्य सूखाग्रस्तों का भाग्य बदल देगा

"नाम" नामक संस्था ने किसान समुदाय को सहायता प्रदान करने हेतु उनके समस्या का स्थाई रूप से समाधान करने का समर्थन किया और ऐसी महिलाओं को कताई चरखा देने का निर्णय लिया जिनके किसान पतियों ने सूखे के कारण आत्महत्या कर ली है।

नाम संस्था के ट्रस्टी ने बताया कि इस संस्था ने महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित समुदाय को सहायता करने के लिए चंदा प्राप्त किया है। हम रोजगार का सृजन करना चाहते हैं इसलिए इस चंदे को सहर्ष स्वीकार करेंगे और कताई कार्य को आसानी से सीखेगें। कताई कार्य सोलर ऊर्जा से संचालित चरखे से किए जाएंगे, इसलिए यह कार्य उनके लिए खर्चीला नहीं होगा। हाल ही में हमने एनएसएस हिलस्प्रिंग इंटरनेशनल स्कूल से चंदा प्राप्त किया, इस धनराशि का खर्च कताई चरखा की खरीदी करने और रोजगार का सृजन करने के लिए किए जाएगा।

प्रथम चरण में यह संस्था 20 महिलाओं को कताई चरखा प्रदान करेगी और तदन्तर में, सोलर चालित कताई चरखा का उपयोग सम्पूर्ण महाराष्ट्र क्षेत्र में किया जाएगा। प्रति कताई चरखा की लागत 47,000/- रुपए है। इस चरखे के माध्यम से खादी सूत का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाएगा तथा कारीगरों की दैनिक आय निश्चित रूप में 200/- रुपए से 400/-रुपए तक होगी। इस संस्था की स्थापना सितंबर 2015 में कलाकार नानापाटेकर और मकरंद अंसुरे द्वारा की गई। इसके अलावा यह संस्था व्यक्तिगत रूप में भी किसानो की मदद कर रही है। संस्था ने किसानों के समक्ष स्थायी रूप में समाधान करने का प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया। इस संस्था के पास सूखा से प्रभावित 133 महिलाओं की सूची है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

शुभा महाजन, नाम ट्रष्टि ने बताया कि हमने ऐसे महिलाओं को पहचानित किया जो आसानी से इन घरेलु कताई चरखा में आसानी से कार्य कर सकती हैं। इन महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हमने कार्यशाला का भी आयोजन किया। खादी सूत, कताई गतिविधियों के माध्यम उत्पादित किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि हमारे मध्य स्थित प्रत्येक व्यक्ति इस प्रमुख कार्य को सम्पन्न करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। इस संस्था ने, सूखा पीडित किसानों को मदद करने के लिए अपने मिशन का प्रथम कदम उठाया। हम अब इस नोबल कार्य को पूरा करने के लिए संभावित मदद में विस्तार करने हेतु लोगों से अपील करते हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र विगत कुछ वर्षो से सूखे से बहुत ही बूरी तरह से प्रभावित है।

सत्य पॉल ने पेश किए मराठवाड़ा खादी परिधान

मुंबई, 25 जनवरी (आईएएनएस)। प्रतिष्ठित डिजाइनर ब्रांड सत्या पॉल ने परिधानों का नया खादी संग्रह पेश किया। इस खादी संग्रह की खास बात यह है कि परिधानों के लिए कपड़े मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों की विधवा खादी बुनकरों ने तैयार किया है।

एक बयान में कहा गया कि इस संग्रह में साड़ी डिजाइनों का संस्करण सीमित है और यह भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

इस संग्रह में शुद्ध खादी की साड़ियों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिसमें खादी के विभिन्न प्रकारों को प्रस्तुत किया गया है।

खादी के विकास के लिए 'नाम फाउंडेशन" द्वारा समर्थित इस संग्रह को यहां बसंत महोत्सव में भी पेश किया गया।

नाना पाटेकर और मराठी फिल्म अभिनेता मकरंद अनासपुरे द्वारा गठित 'नाम फाउंडेशन" का काम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को सुविधाजनक बनाते हुए एक स्थायी और प्रगतिशील समाज का निर्माण करना है, जिसके लिए यह फाउंडेशन बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और रोजगार जैसे विभिन्न मुद्दों पर काम करती है।

- इंडो-एशियन न्यूज सर्विस

ए.जी. राव को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु श्रेष्ठ समन्वयक पुरस्कार

आदित्य शैक्षणिक संस्थान, सुरमपालम, ई.जी. जिला के परिसर में 28 दिसंबर 2015, को ग्लोबल बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर की आधारशिला कार्यक्रम के अवसर पर ग्लोबल बिज़नेस इंक्यूबेशन के प्रबंधन समिति का चयन किया गया और 10 उद्यमियों (खादी और ग्रामोद्योग, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) को सव्यसाछी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

डॉ. वाई. चौधरी, माननीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत सरकार द्वारा उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री चिना राजप्पा और माननीय गृह मंत्री, आंध्र प्रदेश, स्थानीय विधायक और ग्लोबल बिज़नेस इन्क्यूबेटर, जेएनटीयूके, आदित्य शैक्षणिक संस्थान इत्यादि के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए आयोग के विभागीय कार्यालय को एक बेहतर संगठन के रूप में पुरस्कृत किया एवं श्री ए. जी. राव, विकास अधिकारी (एबीएफपीआई) क्षेत्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, विशाखापटनम को प्रधान मंत्री और रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट समन्वयक के रूप में पुरस्कृत किया।

मुख्यालय में कार्यालय अधीक्षकों के लिए हिन्दी कार्यशाला सम्पन्न

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुख्यालय, मुंवई के ढेबर भाई सभाकक्ष में दिनांक 10 दिसंबर, 2015 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । यह कार्यशाला खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कार्यरत अधीक्षकों के लिए आयोजित की गयी थी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उपस्थित अधीक्षकों को कार्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन एवं पत्राचार के बारे में जानकारी देना था।

कार्यशाला का शुभारंभ श्री सिद्धार्थ राय, उप निदेशक/प्रभारी(हिन्दी विभाग) द्वारा कार्यशाला में आमंत्रित व्याख्याता श्री कलीमउल्लाह खान, सहायक निदेशक (राजभाषा), एमटीएनएल, मुंबई का पुष्पगुच्छ देकर किया गया। श्री सिद्धार्थ राय, उप निदेशक/प्रभारी ने भी राजभाषा हिन्दी का पत्राचार एवं टिप्पण का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अधीक्षकों को फाइल पर ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में टिप्पणी लिखने को कहा।

कार्यशाला के विषयानुसार अतिथि वक्ता श्री कलीमउल्लाह खान ने राजभाषा से संबन्धित प्रत्येक विषय को अत्यंत सरलता से बताया। श्री खान ने राजभाषा अधिनियम एवं नियमों की भी विस्तार से जानकारी दी। कार्यालय के दैनिक कामकाज में हिन्दी पत्राचार को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इस पर उन्होने विस्तार से प्रकाश डाला। श्री खान ने अधीक्षकों द्वारा हिन्दी पत्राचार में आने वाली समस्याओं का भी समाधान किया एवं पत्राचार प्रतिशत को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे सुझाव भी दिये।

हिन्दी कार्यशाला में उपस्थित सभी अधीक्षकों ने हिन्दी कार्यशाला को बहुत उपयोगी बताया। इस कार्यशाला में कुल 32 अधीक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला को सफल बनाने के लिए हिन्दी विभाग के सभी कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में श्री कृष्णपाल, वरिष्ठ अनुवादक ने अतिथि वक्ता एवं कार्यशाला में उपस्थित अधीक्षकों को धन्यवाद देकर आभार प्रकट किया।

नासिक में दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यांकों को पूरा करने के लिए दिनांक 17 और 18 दिसंबर, 2015 को आयोग के डॉ.बी.आर.अंबेडकर ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान और नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, त्र्यंबक विद्या मंदिर, नासिक (महाराष्ट्र) में दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

नासिक प्रभाग के अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक श्री अनुराग चौधरी, आई एफएस ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉ.बी.आर.अंबेडकर ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान के निदेशक, श्री रामसिंह, सहायक निदेशक डॉ.राकेश सिंह, विकास अधिकारी श्री वी.के.तिवारी, मुख्यालय मुंबई मे हिन्दी विभाग के प्रभारी श्री कृष्णपाल व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री अनुराग चौधरी ने कहा कि हिन्दी एक सहज और सरल भाषा है, जिसमें काम करना बहुत ही आसान है। इसलिए हम सब को अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य राजभाषा हिन्दी में ही करना चाहिए।

पहले सत्र में व्याख्याता श्री हर्ष मोहन कृष्णात्रे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर पर यूनिकोड की विस्तृत जानकारी दी और उसके बाद अभ्यास भी कराया। उन्होंने भागार्थियों को कार्यालय में पत्राचार के प्रकार की विस्तार से जानकारी दी।

दूसरे सत्र में बीएसएनएल के सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी श्री बी.एस. नखवाल ने प्रतिभागियों को संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रश्नावली को किस प्रकार भरा जाए, इसकी विस्तार से जानकारी दी। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागी अपने कार्यालय प्रभारियों को स्पष्ट रूप से यह जानकारी दें कि संसदीय समिति एवं उच्चाधिकार प्राप्त समिति होती है, इसलिए उसके सामने सूचना प्रस्तुत करते समय अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। श्री नखवाल ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उदाहरण सहित उत्तर दिया।

दूसरे दिन व्याख्याता श्री लोकनाथ तिवारी, हिन्दी अधिकारी, करेंसी नोट प्रेस, नासिक ने राजभाषा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

पहले-दूसरे सत्र में व्याख्याता श्री सुबोध कुमार मिश्र, हिन्दी अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, नासिक ने राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वियन में आने वाली समस्याओं के बारे में सभी प्रतिभागियों से जाना और उनका बड़े रोचक ढंग से समाधान किया।

दूसरे सत्र के अंतिम चरण में प्रतिभागियों से सम्मेलन के संबंध में फीडबैक लिया गया। अपने फीडबैक में प्रतिभागियों ने सम्मेलन की रूपरेखा को उत्कृष्ट बताया और कहा कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बहुत बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन पूरे देश के अलग-अलग राज्य कार्यालयों में किये जाने चाहिए।

राजभाषा सम्मेलन के समापन समारोह पर डॉ.बी.आर.अंबेडकर ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान के निदेशक श्री रामसिंह ने प्रतिभागियों को हिन्दी के प्रति निष्ठा बनाए रखने की अपील की ।

इस दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का संचालन श्री कृष्ण पाल, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, हिन्दी विभाग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई ने किया। उन्होंने कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

विभागीय उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक

दिनांक 8-10 जनवरी, 2016

खादी क्षेत्र की सुर्खियां

प्रधानमंत्री की मन की बात

खादी पर आज करेंगे बात

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. देश में खादी को बढ़ावा देने एवं कारीगरों की समस्या जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात खादी पर करेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी का सपना था कि प्रत्येक भारतवासी स्वावलंबी बने. इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने हमें खादी का मंत्र दिया. सरकार के प्रयासों के बाद राष्ट्रपिता का सपना साकार हो रहा है. खादी के उत्पादों का उपयोग करने के लिए विभिन्न सरकारी संस्थान आगे आ रहे हैं.

■ इनमें रेल मंत्रालय, पुलिस विभाग, भारतीय नौ सेना, डाक विभाग सहित अन्य सरकारी संस्थान शामिल हैं. इन सभी संस्थाओं की मांगों को पूरा करने के लिए खादी के क्षेत्र में काम करने वाले 18 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा. प्रत्येक कारीगर की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी.

■ आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली खादी आज एक फैशन परिधान बन गई है. नवगठित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग नए अवसरों और चुनौतियों को ध्यान में रख... पहल कर रहा है. ऐसे इंतजाम कि...

'Give crop relief to 50% farmers'

■ Continued from Page 1

-tion, he said.

"The biggest thing is that the rate of premium has been kept so low which nobody would have imagined. The rate of premium for kharif crop has been kept at two per cent, while for rabi crop it is one-and-a-half per cent... Now tell me, if any farmer is deprived of the benefits of this scheme, will be not suffer a loss? I want the awareness about this scheme to spread," the PM added.

The Prime Minister also referred to the "Start-Up India" scheme rolled out on January 16 and said it had infused new energy among young people. Mr Modi said there was a wrong notion earlier that the initiative was limited to the sophisticated area of information technology but now it had become clear there were enormous opportunities in this programme for all kinds of sectors and areas, which includes farming. He gave some examples of startups in the farming sector in Sikkim, which was recently declared as an "organic state", India's first. Mr Modi invited more such examples of startup initiatives.

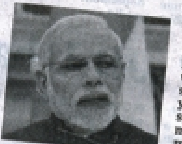

Narendra Modi

The PM referred to the death anniversary of Mahatma Gandhi, that was on January 30, and said people should every year observe a two-minute silence at 11 am in the memory of the country's martyrs.

Talking about the popularising of khadi, on which he had issued an appeal in his first "Mann Ki Baat" in October 2014, the PM said more and more youth were now using khadi products.

Specially mentioning the government's ambitious "Beti Bachao, Beti Padhao" campaign, the PM praised the efforts of the Haryana and Gujarat governments in taking concrete steps to implement it. The number of female births in Ha[ryana] was rising fast as the "Beti Bachao, Beti Padao" campaign had brought about a "real" societal change there, he said.

"Haryana and Gujarat gave importance to the 'daughter' ... This year, the most educated girl of a village was invited to unfurl the national tricolour in a government school (at the Republic Day function). A well-educated 'daughter' was given special importance," he said. Mr Modi had launched the scheme on January 22 last year from Panipat in Haryana, a state which has one of the worst sex ratios in the country. Mahendragarh district in the state was the worst-hit, with ...

मन की बात में खादी और स्टार्टअप पर मोदी का जोर

नई दिल्ली, 31 जनवरी

मन की बात

50% किसानों को देंगे फसल बीमा

खादी को लोकप्रिय बनाएंगे

मन की बात में बोले मोदी

स्टार्ट अप पर भी बोले

25% ही लाभार्थी

02 साल में लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद

बेटियों की सुरक्षा पर मुख्य फोकस रहेगा

■ Praises Haryana, Gujarat for rise in female births

Give crop relief to 50% farmers in 2 years: Modi

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, JAN. 31

Underlining the significance of the recently-announced Crop Insurance Scheme, Prime Minister Narendra Modi said Sunday on his monthly radio show "Mann Ki Baat" that awareness about it should be spread nationwide so that at least 50 per cent of farmers join it within two years.

He also pitched for continued efforts to popularise khadi and awareness to save the girl child and also referred to the recently launched "Start-Up India" programme.

Mr Modi said he needs "maximum help" from people to spread awareness on the Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme that was launched earlier this month. "In our country, a lot is said in the name of farmers. I don't want to get involved in that debate. But farmers face a major crisis. In natural calamities, their entire effort goes waste. His one year goes waste. To give him security, only one thing comes to mind, and that is crop insurance," he said in his first "Mann ki Baat" of 2016.

"In the new year, the Central government has given a given a big gift to farmers — Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme. This scheme has been brought not for the purpose that it should be praised or the PM should be hailed,"

Narendra Modi

● Says 'Start-Up India' not just for high-tech sector, but for everyone

Mr Modi added. He said for so many years, there had been talk about crop insurance, but "not more than 20-25 per cent" of the country's farmers had been able to benefit from such schemes.

"Can we take a pledge that we should connect at least 50 per cent of farmers to this scheme in two years? I need this help from you. Because if a farmer joins the scheme, he will get huge help during a natural calamity," he added.

Mr Modi said this time the scheme had got "wide acceptability because it has been made quite extensive and easy and involves use of technology. Not only this. If something happens to the crop within 15 days after harvest, even then help is assured." Usage of technology will ensure speedy assessment and disbursement of compensa-

■ Turn to Page 5

PM wants 50% farmers to join Crop Insurance Scheme in two years

New Delhi, Jan 31: Highlighting benefits of the just-announced Crop Insurance Scheme, Prime Minister Narendra Modi on Sunday said awareness about it should be spread across the country so that at least 50% of the farmers join it within two years.

In his monthly radio programme 'Mann Ki Baat', he also pitched for continued efforts to popularise Khadi and awareness to save girl child, mentioned about the recently launched 'Start-Up India' programme and talked about the upcoming International Fleet Review to be held in Visakhapatnam.

Modi said he needs the "maximum help" from people about spreading awareness regarding the Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme which was launched earlier this month.

"In our country, a lot is said in the name of farmers. I don't want to get involved in that debate. But farmers face a major crisis. In natural calamity, their entire effort goes waste. His one year goes waste. To give him security, only one thing comes to mind and that is crop insurance," he said in this year's first edition of the monthly radio programme.

"In (the New Year) 2016, the central government has given a big gift to the farmers — Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme. This scheme has been brought not for the purpose that it should be praised or the Prime Minister should be hailed," he said.

The Prime Minister said that for so many years, there has been a talk regarding crop insurance but "not more than 20-25%" of the country's farmers had been been able to benefit from such schemes.

"Can we take a pledge that we should connect at least 50% of the farmers to this scheme in two years? I need this help from you. Because if a farmer joins the scheme, he will get huge help during a natural calamity," he said.

Modi said this time, the scheme has got "wide acceptability because it has been made quite extensive and easy and involves use of technology. Not only this. If something happens to the crop within 15 days after harvest, even then help is assured."

Usage of technology will ensure speedy assessment and disbursement of compensation, he said.

"The biggest thing is that the rate premium has been kept so low which nobody would have imagined. The rate premium for Kharif crop has been kept 2% while for Rabi crop it is one-and-a-half percent.

'50% farmers must get crop insurance in 2 yrs'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Impressed by the enthusiasm of the youth to launch new ventures, Prime Minister Narendra Modi on Sunday said the recently held 'Start-Up India' programme had dispelled the notion that startups were only about IT and added that he was so amazed by the initiatives taken by youngsters in various fields that he would repeatedly like to speak about startups the way he talks about cleanliness.

"It is the common thought that startup means something related to IT, a sophisticated business. This illusion has been broken after the event on startup. Startups around IT are only a small part of it... Startups bring immense opportunities," Modi said in his monthly radio programme 'Mann Ki Baat'.

He gave a number of examples where the youth had launched startups in different parts of the country and appealed to the youngsters to share those concepts with him so that he could talk about them in his 'Mann Ki Baat' again and again. "Your entrepreneurship is our inspiration," Modi said.

During his address, the PM also pitched for expanding the base of the recently announced crop insurance scheme so that at least 50% of farmers were covered under it in two years. He also highlighted benefits of the scheme where farmers would have to pay very low premium. He said that for years there had been talk of crop insurance but "not more than 20-25%" of the country's farmers were able to benefit from such schemes.

"Can we take a pledge that we should connect at least 50% of farmers to this scheme in two years? I need this help from you. Because if a farmer joins the scheme, he will get huge help during a natural calamity," the PM said.

In his nearly 30-minute broadcast, Modi also talked about cleanliness and beautification efforts being made in the country as also the upcoming South Asian Games to be held in Guwahati.

Referring to efforts to beautify places like railway stations, bus stands, temples, mosques and churches, besides keeping them clean, he asked people to send photos displaying this endeavour.

He appealed to people to keep statues clean as a mark of respect to departed leaders.

Prime Minister Narendra Modi at Rajghat on Sunday

Raj women spin success story with solar charkhas

Jaipur: Weaving khadi with solar charkhas has changed the lives of 58-year-old Geeta Devi and 48-year-old Komal Devi of Rajasthan's Dausa. On Sunday, they received accolades from PM Narendra Modi on Mann Ki Baat. The khadi commission had conducted a training programme on the use of solar charkhas that the duo attended. Both felt this innovative version of the charkha was easier to use. — Ashish Mehta

PM: 'Beti Bachao' has worked well in Haryana

New Delhi: The number of female births in Haryana is rising fast as the 'Beti Bachao, Beti Padao' campaign has brought about a "real" societal change there, Prime Minister Narendra Modi said on Sunday, hailing the state which is notorious for female foeticide. Modi, while talking about the Republic Day celebrations, said a unique experiment was carried out in Haryana and Gujarat this time. AGENCIES

For the full report, log on to www.timesofindia.com

खादी क्षेत्र की सुर्खियां

रोजगार पर जोर | नए साल में रेडियो पर पहली बार आए प्रधानमंत्री मोदी

मन की बात में कातिन गीता का खत व खादी

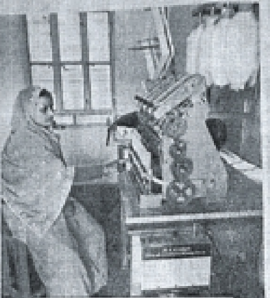

गीता का पत्र

ये भी बोले पीएम

मोबाइल पर सुनें मन की बात

समिति ने दी मशीन की सुविधा

कोमल व गीता के सोच की तारीफ

प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम में दौसा की कातिनों का जिक्र सुनकर सभी प्रफुल्लित

खत में लिखी मन की बात

मजदूरी पर निर्भर परिवार

दौसा में 1400 कातिनें

सरकार से की सब्सिडी की मांग

'Asked family to save money for solar charkha'

►Continued from P 1

Jaipur: "Khoob photu khinch rai hai, Pradhanmantri ji ko dhanyawad. (Many pictures are being clicked. Thanks to the prime minister)," said Geeta, whose residence near Anaj Mandi in Dausa was thronged on Sunday by several mediapersons and locals.

Asked about her experience with 'solar charkha', she said, "Tailoring and weaving is our ancestral profession. With the continuous use of charkha one gets a pain in the shoulder in old age. But this is easier to operate. Not only that, earlier I used to earn Rs 80 per day but now I am making Rs 150 to Rs 200," she said.

"I am told that this 'charkha' costs about Rs 40,000. At home I have the manual one, and I have asked my family members to save some money to purchase the solar one. It is really good," she said.

Komal Devi with her solar charkha at Dausa

Modi lauds two women from Raj in Mann Ki Baat

Ashish.Mehta@timesgroup.com

Jaipur: Prime Minister Narendra Modi on Sunday heaped praises on two women from Rajasthan in his weekly Mann Ki Baat address to the nation. While talking about how khadi can provide jobs to crores of Indians, he mentioned Geeta Devi (50) and Komal Devi (40), both from Dausa, for weaving the cloth with 'solar charkhas'.

Geeta Devi

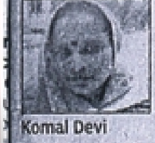

Komal Devi

Geeta Devi and Komal Devi began attending training sessions on 'solar charkhas' at the office of Khaadi Samiti in Dausa three months ago, part of pan-India initiative of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC).

"Both mastered the skill with 'solar charkhas'. These are easier to work with than the conventional 'charkhas' as one does not need to turn the wheel manually. This is done by solar energy. Both the women were happy and had written about their experience to Prime Minister Narendra Modi recently," said Anil Sharma, secretary of Khadi Samiti of Dausa while

► Bring 50% farmers under insurance cover: PM, P 7

From khadi to crop insurance, Modi connects with all

dna correspondent @dna

New Delhi: Trying to make his monthly radio broadcast as broad-based as possible, Prime Minister Narendra Modi not only touched upon varied issues ranging from Khadi to Start-ups, save the girl child to crop insurance scheme and cleanliness but also talked about upcoming events – International Fleet Review in Vishakhapatnam and SAARC Sports competition at Guwahati.

In the 16th edition of his Mann Ki Baat that clocked a little over 28 minutes, PM Modi did not speak on any of the controversial and raging issues.

Cong slams PM for not mentioning Vemula case

Keeping up the offensive on the Rohith Vemula suicide issue, Congress on Sunday lashed out at PM Narendra Modi for not taking any action against Union ministers Smriti Irani and Bandaru Dattatreya. Party's senior spokesman Anand Sharma regretted that the Prime Minister did not even refer to the issue in his 'Mann Ki Baat' radio programme.

Invoking Mahatma Gandhi and Sardar Patel, he heralded Khadi as having the power to generate employment for crores of people and said, "To fulfil demand for Khadi, can you imagine that additional jobs of 18 lakh man days will be generated."

Modi also called for technological up-gradation of the industry and appreciated that the solar energy was now being used to power the Charkha (loom).

Using the platform to highlight benefits of the just-announced Crop Insurance Scheme, PM said awareness about it should be spread across the country so that at least 50 per cent of the farmers join it within two years.

"I need maximum help from people about spreading awareness regarding the Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme which was launched earlier this month..... a lot is being said in the name of farmers. I don't want to get involved in that debate," said Modi.

Modi said "The biggest thing is that the rate of premium has been kept so low which nobody would have imagined. The rate of premium for Kharif crop has been kept 2 per cent while for Rabi crop it is one-and-a-half per cent. Now tell me, if any farmer is deprived of the benefits of this scheme, will he not suffer loss?"

PM wants 50 per cent of farmers to join Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme

खादी क्षेत्र की सुर्खियां

आज — वाराणसी महानगर

बेरोजगारी निवारण में खादी ग्रामोद्योग की बड़ी भूमिका- कलराज मिश्र

१७ दिवसीय खादी मेला संपन्न, एक करोड़, ९८ लाख का हुआ कारोबार

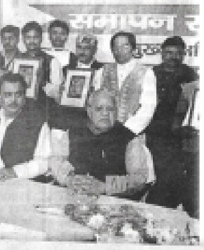

03 हिन्दुस्तान • वाराणसी • गुरुवार • 14 जनवरी 2016

दिल्ली जैसा खादी भवन काशी में भी बनेगा

वाराणसी | वरिष्ठ संवाददाता

कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री

केन्द्रीय लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने कहा है कि दिल्ली की तर्ज पर बनारस में भी खादी भवन बनेगा। भवन में फूडकोर्ट के अलावा हर साल खादी के फैशन शो भी आयोजित किए जाएंगे।

गुरुवार को खादी ग्रामोद्योग आयोग की ओर से बीते 28 दिसम्बर से चल रही प्रदर्शनी के समापन पर पहुंचे मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में 148 खादी भंडारों को संवारा जाएगा। मौके पर मेयर राम गोपाल मोहले व विधायक रवीन्द्र जायसवाल ने भी विचार रखे।

कर्तव्य बोध कर समाज को बढ़ाएं: कर्तव्य बोध समाज को आगे बढ़ाने का सही कदम है। इससे व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कलराज मिश्र ने यह बात रोटरी क्लब बनारस के कार्यक्रम में होटल एचएचआई में कही। उन्होंने शिव झुनझुनवाला, सिद्धार्थ गुप्ता, भोलानाथ बरनवाल, भारती मधोक, अशोक पाण्डेय, डॉ. हेमंत गुप्ता, मीरा ओहरी, गोदावरी सिंह व डॉ. रामसुधार सिंह को वोकेशनल एक्सिलेन्स अवार्ड दिया। मौके पर बीएचयू वीसी प्रो. जीसी त्रिपाठी, दीनानाथ झुनझुनवाला, मंडलाध्यक्ष वेद प्रकाश थे। स्वागत चंद्रशेखर कपूर, आभार रोहित कपूर तथा संचालन अंकिता खत्री ने किया।

14.01.2016 अमर उजाला — मेरा शहर | वाराणसी | बृहस्पतिवार | 3

तेलियाबाग में बनेगा अत्याधुनिक खादी भवन

एमएसएमई मंत्री ने कहा, राज्यों के प्रमुख शहरों में लगेगी खादी प्रदर्शनी

खादी मेले का समापन

मेले में हुआ दो करोड़ का कारोबार

inext, Varanasi, 14 January 2016 | 5

बनारस में बनेगा खादी भवन

केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, खादी प्रदर्शनी के समापन समारोह में हुए शामिल

अमर उजाला — वाराणसी | बृहस्पतिवार | 14 जनवरी 2016

एमएसएमई मंत्री बोले, शहरों में लगेगी खादी प्रदर्शनी

तेलियाबाग में बनेगा आधुनिक खादी भवन

राज्यस्तरीय खादी प्रदर्शनी के समापन समारोह में पुरस्कृत लघु उद्यमी। साथ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र।

वाराणसी (ब्यूरो)। खादी की पहचान को सशक्त बनाने के साथ ही इसकी ब्रांडिंग व प्रचार-प्रसार के लिए अत्याधुनिक भवन का निर्माण तेलियाबाग स्थित परिसर में किया जाएगा। साल 2016 के अंत तक इस भवन की नींव रखी जाएगी। इसके साथ ही खादी को जन-जन तक पहुंचाने व बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्यों के जिलों में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उक्त बात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मंत्री कलराज मिश्र ने बुधवार को तेलियाबाग में चल रहे खादी मेले के समापन अवसर पर कही।

खादी मेले में दो करोड़ का कारोबार

वाराणसी। 15 दिवसीय खादी प्रदर्शनी में बिक्री का लक्ष्य एक करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। इसके सापेक्ष करीब दो करोड़ का कारोबार हुआ। लगभग दो गुने का कारोबार हुआ।

भवन का निर्माण किया जाएगा। खादी ग्रामोद्योग वस्तुओं की बिक्री के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य की राजधानियों तथा बड़े शहरों में खादी प्लाजा खोलने का निर्णय लिया है।

विधायक रवींद्र जायसवाल ने ...

दैनिक जागरण | वाराणसी, 14 जनवरी 2016 | 9

बनारस में बनेगा मॉडल खादी भवन

प्रदर्शनी के समापन पर पुरस्कृत दुकानदारों संग केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र।

समलैंगिक के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए

- खादी को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले में लगाई जाएंगी प्रदर्शनी

आजादी में खादी का योगदान

वाराणसी राष्ट्रीय सहारा | www.samaylive.com

खादी को बढ़ावा के लिए अत्याधुनिक भवन का होगा निर्माण : कलराज

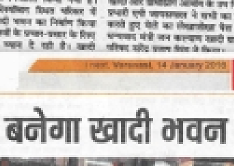

खादी क्षेत्र की सुर्खियां

अमर उजाला | लखनऊ | बृहस्पतिवार | 7 जनवरी 2016

मेक इन यूपी से ही मेक इन इंडिया संभव

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र बोले- उद्योग राज्य का विषय, केंद्र कर रहा पूरा सहयोग

एनपीए रोकने में सहयोग करेंगे बैंक

इंडस्ट्री का बन रहा प्रोफाइल

खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी योजनाओं का करें प्रसार

कई चेहरे हैं सीएम की उम्मीदवारी के लिए

---

hindustantimes | uttar pradesh | 05

HINDUSTAN TIMES, LUCKNOW
THURSDAY, JANUARY 07, 2016

25 livelihood incubation centres to help train youths in UP, says Kalraj

HT Correspondent

LUCKNOW: The union ministry of micro, small and medium enterprises is on its way to setting up 25 livelihood incubation centres in Uttar Pradesh under its prestigious programme to provide job-oriented training to rural and urban youths.

These centres would come up on the campus of engineering colleges governed by the Abdul Kalam Technical University and the state government run degree colleges, said union minister for micro small and medium enterprises Kalraj Mishra who was in the state capital to preside over a workshop of the Khadi and Village Industries Commission.

In rural parts of the state, the livelihood incubation centres will come up on land provided by the state government.

The MSME ministry plans to set up 100 such centres across the country. The Uttar Pradesh government has allocated land for 10 such centres in various districts of the state. Two such centres in Varanasi and Deoria have started working.

"In a bid to provide skill manpower to industries, the union government has decided to set up 100 livelihood incubation centres across the country. In Uttar Pradesh, 25 such centres will come up where youths will be imparted various vocational training — both technical and non-technical," Mishra told newspersons.

With assembly elections round the corner in Uttar Pradesh in mid 2017, the union minister emphasised that Uttar Pradesh was on the Centre's priority list.

Youths passing out from these centres would be provided loans from nationalised banks to start their own venture and those opting for jobs would be provided all help in getting a good placement, Mishra added.

At these centres girls would be trained in fashion designing, tailoring, and beautician course among other vocational programmes.

The ministry has set a target of training eight lakh youths across the country at the livelihood incubation centres.

Taking forward Prime Minister Narendra Modi's Digital India programme, the MSME is also planning to set up a digital employment exchange for industries.

"At these employment exchanges, the youths will be provided job-oriented computer training to fulfil the requirement of the industries," Mishra said.

Talking about the Prime Minister's Employment Generation Programme, Mishra stated that a scheme to encourage start-ups for innovation and entrepreneurship in rural and agriculture based industry was also underway.

In Lucknow, the livelihood incubation centres would come up at Dr Shakuntala Misra National Rehabilitation University, IET campus and Mahila Vidyalaya Post Graduate College.

Union minister Kalraj Mishra addressing the gathering at Ganna Sansthan in Lucknow on Wednesday. DEEPAK GUPTA/HT PHOTO

ALLEGATIONS BASELESS: MIN

LUCKNOW: Union minister Kalraj Mishra on Wednesday refuted the UP government's claim that the centre was not providing funds to it.

"Assembly elections are round the corner. So, these allegations are politically motivated just to seek the attention of the people," Mishra said.

Substantiating his claim, Mishra stated, "The state government has been able to spend only Rs 92 crore out of Rs 120 crore." HTC

नवभारत टाइम्स | लखनऊ दरबार

www.lucknow.nbt.in

दो महीने में कैसे लगेंगी 3000 यूनिटें?

'मेरे बारे में सोचने के लिए साधुवाद'

---

the pioneer

LUCKNOW | THURSDAY | JANUARY 7, 2016

25 livelihood business incubation centres identified for UP: Kalraj

'BJP is fully prepared for UP Assembly elections'

लखनऊ, 7 जनवरी 2016 दैनिक जागरण | 11

चुनाव देख आरोप लगा रही सपा सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की राज्यस्तरीय कार्यशाला में शामिल होने लखनऊ आए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने बुधवार को जब बताया कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाली इस योजना की सफलता के लिए वह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सहयोग का आग्रह करेंगे तो पत्रकारों ने सवाल उठा दिया कि राज्य सरकार तो उल्टे केंद्र पर असहयोग का आरोप लगा रही है। कलराज बोले, योजना की मार्जिन मनी के लिए प्रदेश सरकार को 120 करोड़ रुपये दिए थे पर वह सिर्फ 92 करोड़ रुपये खर्च कर पाए, लेकिन कह रहे हैं और दो... । चुनाव आ रहा है, इसलिए आरोप तो ये लगाएंगे ही।

कलराज ने बताया कि दो प्रमुख योजनाओं एस्पायर व पीएमईजीपी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एस्पायर के तहत देश में 100 से अधिक लाइवलीहुड इनक्यूबेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। वाराणसी व देवरिया में शुरू ऐसे दो केंद्रों में युवाओं को विभिन्न मशीनों से प्रशिक्षण देकर स्किल्ड बनाया जा रहा है। लखनऊ में अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि, शकुंतला मिश्र विवि व महिला महाविद्यालय में भी ऐसे केंद्र शुरू करने की कोशिश है। वह मुख्यमंत्री से प्रदेश में 10 ऐसे केंद्र शुरू करने की बात करेंगे। उन्होंने प्रमुख सचिव रजनीश दुबे के हवाले से बताया कि प्रदेश में 25 केंद्रों के लिए जगह चिह्नित की गई है। अन्य प्रदेशों की तरह यूपी में फरवरी में रोजगार मेला लगाया जाएगा। उद्योगों व अनुभवी कामगारों को मिलाने के लिए पार्ट-अप ... होगा।

बोले कलराज

- प्रदेश में खर्च नहीं हो पा रही केंद्र से मिली रकम

गन्ना संस्थान में कार्यशाला में लोगों को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र

सीएम के लिए कई चेहरे

पत्रकारों ने जब 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कलराज मिश्र से सवाल पूछा कि क्या प्रदेश में भाजपा की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश संभावना है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। प्रदेश भाजपा में इसके लिए कई चेहरे हैं।

पहले मेक इन यूपी...

गन्ना संस्थान सभागार में रोजगार सृजन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलराज मिश्र ने बुधवार को कहा कि सूक्ष्म व लघु उद्योगों से ही देश विकसित होगा, लेकिन इसके लिए केंद्र व प्रदेश में समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा पहले 'मेक इन यूपी' होगा तब ही 'मेक इन इंडिया' साकार हो पाएगा। मंत्री ने कहा यूपी में जो पैसा मांगिए, हम देने को तैयार हैं, लेकिन सदुपयोग होना चाहिए। इससे पहले योजना के अमल से जुड़े विभागों के प्रतिनिधियों से सुझाव-शिकायतें सुनने के बाद कलराज ने कहा कि ज्यादा आवेदन आना कोई परेशानी की बात नहीं है।

डिजिटल इंप्लायमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्री कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। उद्योग आधार नंबर के लिए भी 1.28 पंजीकरण हो चुके हैं।

बैंक बन रहे बाधा : कार्यशाला में शामिल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंकों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने योजना के अमल में जो कठिनाइयां बतायीं, उनमें बैंकों से हो रही असुविधा प्रमुख थी।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम सचिव अनूप कुमार पुजारी ने कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों से कहा कि योजना के डिजाइन में फाल्ट ... ती, लेकिन इंप्लीमेंट... ना होगा।

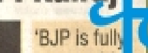

Khadi India
स्वस्थ जीवन का प्राकृतिक मार्ग
बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056 वेबसाइट : www.kvic.org.in
भारत में हम रोजगार सृजन करते है तथा समृद्धि बुनते हैं